हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़

तिथि 22 जुलाई 2024 **समय 1810**

- केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
- वित्त वर्ष 2024 -2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर साढ़े 6 से 7 प्रतिशत
- के बीच रहने का अनुमान लगाया गया ।
- केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है ।
- केन्द्र सरकार ने कहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।
- हरियाणा के मुख्य सचिव ने हरियाणा कौशल रोज़गार निगम को विभागों की कौशल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकरियों की एक व्यापक सूची तैयार करने के निर्देश दिए ।
- जींद जिले में गढ़ी पुलिस ने 2 स्थानो से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 किलोग्राम गांजा और साढ़े 8 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर साढे छह से सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है।महंगाई के बारे में रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति की मुख्य दर साढ़े चार प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए 2024 में मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत और 2025 में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर वर्ष 2020 की तुलना में बीस प्रतिशत अधिक रही है। ये ऐसी उपलब्धि है, जो गिनी-चुनी अर्थव्यवस्थाएं हासिल कर पाई हैं। इस वर्ष भी वृद्धि दर अच्छी रहने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी और बहुआयामी गरीबी में कमी और श्रम बल भागीदारी में बढ़ोतरी के साथ विकास समावेशी रहा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की वास्तविक सकल घरेलु उत्पाद दर में वित्त वर्ष 2024 में 8.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है और लगातार तीसरे वर्ष ये सात प्रतिशत से अधिक

दर्ज हुई है। इसमें स्थिर खपत, मांग और निवेश में निरन्तर सुधार का योगदान है। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कुल करों में वित्त वर्ष 2024 के दौरान 19.1 प्रतिशत इजाफा हुआ है। सर्वेक्षण में 2024 के लिए वैश्विक व्यापार परिदृश्य सकारात्मक बताया गया है

केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लागू किया था।भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 58 वर्ष पहले जारी यह असंवैधानिक आदेश मोदी सरकार ने वापस ले लिया है।क़ाबिले ग़ौर है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ सहित कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के RSS से जुडने पर लगी पाबंदी पहले ही हटा दी है।

केन्द्र सरकार ने है दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रशन के उत्तर में बताया कि जून, 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दो ज्ञापन प्राप्त हुए थे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

करने के लिए नौकरियों की एक व्यापक सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के निर्देश दिए हैं।हरियाणा कौशल रोजगार निगम बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री प्रसाद ने निगम को और अधिक पेशेवर तरीके से काम करने और बिना देरी के मानव शक्ति की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।बैठक में बताया गया कि निगम विदेश मंत्रालय के अधीन प्रवासी संरक्षक से भर्ती एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जो उसे अपने स्तर पर विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को नियुक्त करने में सक्षम बनाएगा। निगम ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से विदेश में नियुक्ति के इच्छुक 228 लोगों का चयन किया है।बैठक में यह भी बताया गया कि निगम ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों एवं में एक लाख 25 हजार कर्मियों को तैनात किया है। इनमें से 36,000 से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग से और 34,700 से अधिक पिछड़ा वर्ग से हैं।

जींद जिले में गढी पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 किलोग्राम गांजा और साढ़े आठ किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है।गढ़ी चौकी प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर धमतान साहिब निवासी मदन को भुल्लन मोड़ से गिरफ्तार किया गया , आरोपी की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के कट्टे में रखा 10 किलो ग्राम गाँजा बरामद हुआ। इसी तरह एक गुप्त सूचना के आधार पर गांव गढी से दो आरोपियों को काबू करके उनके कब्जे से कुल 8 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया । आरोपियों की पहचान अनाज मंडी डिन्डोली निवासी जगतार सिहं व विशाल के तौर पर हुई है ।

रोहतक में आज वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव में रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने पौधा लगा कर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत तीन एकड़ भूमि में सघन वन पद्धति से 40 प्रजातियों के 10 हजार औषधीय, फलदार व छायादार पौधे लगाए जाएंगे।रोहतक में पौधारोपण अभियान के लिए स्थानीय गोहाना सड़क पर स्थित वीटा चौक से जींद मार्ग की ओर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की हरित पट्टी को चुना गया है।उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि वन विभाग ने रोहतक जिला में पौधरोपण के लिए 5 लाख पौधे तैयार किए हैं। आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी की तकनीक के तहत सघन वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा।वहीं वन विभाग के उप संरक्षक सुंदर सिंह ने बताया कि मियावाकी एक सघन और तेजी से विकसित होने वाली वनीकरण तकनीक है । उन्होंने बताया कि तीन साल तक पौधों के संरक्षण के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

कैथल जिले की ग्राम पंचायत माघो माजरी के सरपंच राजकुमार फौजी ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गांव वासियों और वन विभाग के सहयोग से 500 फल, फूल और छायादार पेड़-पौधे लगाए। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि 500 पेड़ लगाने से गांव में हरियाली बढ़ेगी ।